THE VICE-CHAIRMAN (Shrimati Kamla Sinha): The topic is injustice and harassment to the. Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, kindly come to the topic and be brief.

SHRI V. P. DURAISAMY: I am on the topic.

Madam, our Constitution provides for safeguarding the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is why rules were also framed and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Council was constituted. This Council is meant to protect the interests of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees working in banks and in Government organisations. Whenever they face any problem, they sit with the Administration "and find out solutions. The Council's function is that of watch-dog to safeguard the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But, Madam, the Syndicate Bank and the United Bank never invited the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Council for an negotiations. In spite of repeated requests of the Council and their associations, the bank officers have not been responding properly. They are not treating the Scheduled Castes and Scheduled Tribes associations on par with other associations. That is why the General Secretary of the United Bank also has been repeatedly requesting the Administration for a meeting. He has never been invited for any negotiation or any regular meeting which is conducted by its Administration.

It is crystal clear that the authorities of the aforementioned banks are flagrantly violating the rules with impunity, and their intention is malafide. While the United Front Government is committed to the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and is doing a lot for them, by promoting their interests, even then some officers and the bank authorities are acting against the interests of the Government. The active members of the Scheduled Castes and Scheduled tribes Welfare Associations arc very often given vindictive transfers to rural areas, instead of their grievances being redressed. The active members of the Association are approaching the bank authorities quite often, in order to protect the interests of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees. Very often, they are arguing with the authorities to safeguard the interests of these employees. In view of this position, the members of the Association are often disturbed and are transferred to rural areas. The Scheduled Caste and Scheduled "Tribe employees and the OBC employees arc also not given promotions, as per the Government guidelines. Those employees who are serving as sweepers, arc not promoted as Class IV employees. Under these circumstances, I request the Government to direct the authorities of banks, particularly, the Syndicate Bank and the United Bank, to hold regular meetings with the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Welfare Councils and redress all their grievances. The Government should also take stern action against the officials who flout the guidelines of the Government. Thank you.

Cover-up Operation to stall Enquiry into Emergency Restoration System Import Deal by Power Grid Corporation of India

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से एक गम्भीर मामला आपके समक्ष लाना चाहता हूं। ऊर्जा मंत्रालय की पावर ग्रिड कारपोरेशन ने अभी हाल ही में इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम 34 करोड़ रुपये की लागत से इम्पोर्ट किया है। यह वेस्टर्न और नार्दर्न रीजन के लिए इम्पोर्ट किया गया है। यह खरीदी भी वेस्टर्न और नार्दर्न रीजन के लिए की गई है। समाचार पत्रों के अनुसार विंध्याचल धुले ट्रांसमिशन लाइन जो एक अमरीकी कम्पनी लिंडसे से खरीदी गई, इसकी दामों में भी काफी गड़बड़ी है। ऊर्जा मंत्रालय ने पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम के आयात के साथ विंध्याचल और धुले को टर्न-की कंट्रेक्ट दिया है और लिंडसे ने जिन वेंडर्स के माध्यम से यह मशीने भेजी हैं उनको काफी

रियायतें अपने भुगतानों में दी है। 4.53 मिलियन का 75 प्रतिशत के॰ई॰सी॰, एस॰ए॰ई॰ इंटरनेशनल और एबेनगोल आ जो स्पेन की एक कम्पनी है, उनके माध्यम से इन उपकरणों के लिए यु॰एस॰ए॰ की लिंशसे कम्पनी को भुगतान कर दिया है। नियत समय से पहले भुगतान पावर ग्रिड कारपोरेशन और वेंडर्स के बीच में हुए करार के विरुद्ध है। यह बड़े खेद की बात है और दुख की बात है कि पता नहीं किस के आदेश से पैसों का भुगतान इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम के आयात के लिए समय से पूर्व करार के विरुद्ध किया गया। करार के मुताबिक वर्क साइट पर रेल्वे रिसीट या लारी रिसीट के बाद भुगतान किया जाना था। वेंडर्स से पावर ग्रिड कारपोरेशन ने 14 या 18 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर सिर्फ 7.1 प्रतिशत ब्याज चार्ज किया है। पावर ग्रिड ने अपने एक अधिकारी को लिंडसे जो अमरीका की कम्पनी है इस उपकरण की तकनीकी क्षमता की जांच के लिए अमरीका भेजा लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये अधिकारी जो कि क्वालिटी कंट्रोल विंग का होना चाहिये था, उसकी जगह एक गैर तकनीकी अधिकारी था। यह सारी अनियमितताएं एक गम्भीर मामले की शुरूआत करती है और मैं इस सदन के माध्यम से आपके माध्यम से चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्रालय इन सारी गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच करे और अगर जरूरत पड़े तो सी॰बी॰आई॰ से जांच करवाए। यह एक गम्भीर मसला है। इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट सदन में रखें और सदन को ज्ञात कराएं और यह सुनिश्चित करें कि और कोई अनियमितता इस मामले में नहीं होगी। धन्यवाद।

Freedom-Fighters is their Status and Problems on the Fiftieth Anniversary of our Independence

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब): मोहतरम वाईस चेयरमैन साहिबा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे हिंदुस्तान की आजादी के लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर जो थे उनकी समस्याएं और 50 साल बाद उनका हमारे समाज में क्या स्टेटस है इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। इसके साथ मेरे चंद साथी जो अभी तक उन फ्रीडम फाइटर्स की बात को सुनने के लिए यहां बैठे हैं मैं उनका भी बहुत ममनून हूं और मशकूर हूं कि वे यहां तशरीफ रखते हैं। मैडम, वाईस चेयरमैन जो कोमें अपने शहीदों को और अपने आजादी के लड़ने वालों को भूल जाती हैं वे इतिहास के पन्नों में गुम हो जाती हैं। 50 साल के बाद जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी जो आज जिंदा शहीद, फ्रीडम फाइटर्स इस देश में जिंदगी की आखिरी दिन पूरे कर रहे हैं उनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि उनकी हालत जो 50 साल पहले थी उससे अच्छी तो क्या होगी, अगर मैं यह कहूं कि बद से बदतर हो गयी है तो मैं उनके जज्बात की तर्जुमानी करूंगा। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने एक सुनहरा खाका तैयार किया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आजादी के बाद भी हिंदुस्तान में ऐसे गरीब लोगों की बस्तियां होंगी जहां इन्सानों के बच्चे गंदगी के ढेरों से छोटे छोटे निवाले ढूढने के लिए जानवरों के साथ छीना झपटी करेंगे। उनको तो यकीन था कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। आज शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना सिर्फ एक रिचुअल और सिर्फ एक रस्म बाकी रह गयी है। हम उस रस्म को निभाते हैं हर साल और उसके बाद भूल जाते हैं उन आजादी के परवानों को जो आज जिंदा शहीद बने हुए हमारे देश में रहते हैं और वे कभी कभी तो यह कहते हैं कि—मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। आज मुफलिसी में, दर्द में, दुख में जिस तरीके से बहुत से आजादी के परवाने रहते हैं उस बात ने मुझे मजबूर किया है कि इस इश्यू को मैं हाउस के सामने रखूं।

आज प्रायमरी स्कूल के बच्चों को ले लीजिए उनको छोटे फिल्म एक्टर और बड़ी से बड़े फिल्म एक्ट्रेस का नाम तो याद होगा लेकिन उनसे अगर आप यह पूछिए कि हिंदुस्तान की लड़ाई के लड़ने वालों का नाम क्या था और वे कौन थे जिन्होंने तख्ताएदार पर जाकर हिंदुस्तान की आजादी लड़ी, वे कौन लोग थे जो जवानी में जेल की सलाखों के पीछे गए, और उस वक्त जेल की सलाखों से बाहर आए जब तपेदिक से, कैन्सर से, टी॰बी॰ से उनके घर बरबाद हो गए, तो आज के स्कूल के विद्यार्थियों को उन शहीदों के, उन आजादी के परवानों के, उन फ्रीडम फाईटर्स के नाम मालूम नहीं होंगे। उन्होंने हिनदुस्तान को आजाद तो देख लिया लेकिन उनको उन बहादुरों के नाम नहीं पता जिन्होंने अपनी जिंदगी की कुरबानियां देकर देश को आजादी के नजदीक लाया।

मैं आपकी वसातत से सरकार को कहना चाहता हूं कि आज देश की तारीख में स्कूलों में, कालेजों में उनके सिलेबस में इंग्लिश हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है। मुगल दौर की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है लेकिन आजादी का जो इतिहास है वह उन स्कूलों के सिलेबस में न शामिल है और न कालेजों के सिलेबस में शामिल है और किसी यूनिवर्सिटी ने कभी इस बात की तरफ तवज्जह भी नहीं दी कि हमने उस इतिहास को क्या देखना है कि लार्ड क्लाइव कौन था, लार्ड कर्जन कौन था।